

वैश्विक धरातल पर निजीकरण से प्रभावित कामकाजी महिलायें : एक मूल्यांकन

Dr. Sadhana Agarwal

Assistant Professor, Hindi Department, D.B.S. College, Govind Nagar, Kanpur, India

सार

निजीकरण व्यवसाय, उद्यम, एजेंसी या सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र (राज्य या सरकार) से निजी क्षेत्र (निजी लाभ के लिए संचालित व्यवसाय) या निजी गैर-लाभ संगठनों के पास स्थानांतरित होने की घटना या प्रक्रिया है। एक व्यापक अर्थ में, निजीकरण राजस्व संग्रहण तथा कानून प्रवर्तन जैसे सरकारी प्रकार्यों सहित, सरकारी प्रकार्यों के निजी क्षेत्र में स्थानांतरण को संदर्भित करता है। शब्द "निजीकरण" का दो असंबंधित लेनदेनों के वर्णन के लिए भी उपयोग किया गया है। पहला खरीद है, जैसे किसी सार्वजनिक निगम या स्वामित्व वाली कंपनी के स्टॉक के सभी शेयर बहुमत वाली कंपनी द्वारा खरीदा जाना, सार्वजनिक रूप से कारोबार वाले स्टॉक का निजीकरण है, जिसे प्रायः निजी इक्विटी भी कहते हैं। दूसरा है एक पारस्परिक संगठन या सहकारी संघ का पारस्परिक समझौता रद्द कर के एक संयुक्त स्टॉक कंपनी बनाना।

परिचय

उदारीकरण के दौर में आर्थिक सुधारों के साथ जो चीज़ सबसे ज़्यादा उभरकर सामने आई वह थी सरकारी क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के ज़रिए सरकार ने निजी कंपनियों के साथ करार कर उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल एवं अन्य क्षेत्रों में शामिल किया। इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि इससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अगर, स्वास्थ्य की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर की मुनाफ़ाखोरी, महंगी दवाइयां, [1,2] हॉस्पिटल के खर्च आदि ने लोगों को आर्थिक रूप से लगातार कमज़ोर किया है। स्वास्थ्य में इस मॉडल के असर को गहराई से समझने के लिए हमने पेशे से शोधकर्ता बिजोया रॉय से बात की। वे नई दिल्ली के महिला विकास अध्ययन केन्द्र (CWDS) से जुड़ी हुई हैं। बिजोया का शोध भारत में स्वास्थ्य सेवा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर केंद्रित है। उनकी रूचियों ने उन्हें स्वास्थ्य सेवा, असमानताओं, जेंडर और हिंसा में नवउदारवादी नीतियों के प्रभाव को करीब से समझने के लिए प्रेरित किया। टीटीई के साथ इस बातचीत में, बिजोया विश्लेषण करती हैं कि कैसे पीपीपी ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को आकार दिया है, राज्य की भूमिका को फिर से परिभाषित किया है, [3,4] और उदारीकरण के बाद के भारत में दशकों से स्वास्थ्य को किस तरह प्रभावित किया है। विभिन्न देशों में यह देखा गया है कि जब स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण किया जाता है, तो महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वे सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कनफेडरेशन की छग इकाई की ओर से खुर्सीपार स्थित स्कूल में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का 53वां साल मनाया गया। स्व सहायता समूह की महिलाओं की क्लस्टर मीटिंग की गई। इसमें बैंकों के अफसरों और समूह की महिलाओं ने बैंकों के निजीकरण का विरोध किया। बैंक बचाओ-देश बचाओ के नारे लगाए। वक्ताओं ने बैंकों के निजीकरण से होने वाले नुकसान गिनाए। कहा कि बैंकों के निजीकरण से बेरोजगारी बढ़ेगी। [5,6] राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं कम होंगी। लोगों की जमा पूंजी सुरक्षित नहीं रहेगी। कन्फेडरेशन के प्रदेश महासचिव वाई गोपाल कृष्ण ने कहा कि बैंक ने राष्ट्रीयकरण के बाद देश के विकास में अहम भूमिका निभाई। गांव और दूर-दराज क्षेत्रों तक सड़कों के माध्यम से पहुंच बनाई। ग्रामीण भारत का स्वरूप बदला। कृषि, लघु उद्योग, हरित और श्वेत क्रांति के साथ ही प्रधानमंत्री जन-धन योजना, मुद्रा योजना, पीएम आवास योजना, स्टैंडअप इंडिया के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसका निजीकरण किया जा रहा है। इससे राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखी गई जमा पूंजी सुरक्षित नहीं रहेगी। सरकार द्वारा दी गई गारंटी समाप्त हो जाएगी। [7,8]

शिक्षा का निजीकरण : देश में लगातार निजीकरण बढ़ता दिख रहा है। रेलवे से लेकर हवाई जहाज़ तक। सब्जी मंडी से लेकर किराने की दुकान तक। हर तरफ निजीकरण का विस्तार हो रहा है। अब शिक्षा का क्षेत्र पूरी तरह से अंबानी-अडानी जैसे उद्योगपति के हाथ में चला जाएगा। सरकार लगातार ऐसी नीतियां लागू कर रही है। जिससे हमारे देश के सरकारी स्कूलों का निजीकरण और शिक्षा का निजीकरण किया जाना संभव लगने लगा है। सोशल मीडिया पर एक महिला शिक्षक का वीडियो जमकर वायरल है। महिला शिक्षक डिजिटल क्लास के दौरान छात्रों को पढ़ाते हुए बता रही हैं कि हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई नीति लागू होने वाली है। जो जल्द ही देश के अन्य राज्यों तक भी पहुंच जाएगी। [9,10] हरियाणा सरकार के मुताबिक राज्य में जिस परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार से कम होगी। उन परिवार के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उनको 500 रुपये सरकार को

देना होगा। अगर वही बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो सरकार उनको अपने पास से 1100 रूपये देगी। महिला शिक्षक हरियाणा की नई शिक्षा नीति पर छात्रों को समझाते हुए कहती है कि कौन परिवार चाहेगा कि 500 रूपये देने के बाद उनका बच्चा सरकारी स्कूल में जाए। जब सरकार 1100 रूपये प्राइवेट स्कूल जान छात्रों को अपने पास से दे रही है। ज़ाहिर है हर परिवार अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल ही भेजेगा। [11,12] वह आगे बताते हैं कि ये सरकार की एक चाल है राज्य में शिक्षा का पूरी तरह से निजीकरण करने का। छात्रों को पढ़ाते हुए महिला शिक्षक बता रही है कि धीरे-धीरे सरकारी स्कूल खाली हो जाएंगे। शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा। कोई भी बच्चा उन सरकारी स्कूलों में नहीं जाएगा। अब अगर किसी परिवार में 4 बच्चे हैं तो वो उनको सरकारी स्कूल क्यों भेजेगा जहां उसको 2000 हजार रूपये सरकार को अपने पास से देना पड़े। जबकि प्राइवेट स्कूल भेजने पर 4 हजार से अधिक सरकार परिवार को अपने पास से देगी। ज़ाहिर है हर परिवार अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजेगा। कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल नहीं भेजना नहीं चाहेगा। [13,14]

भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा सरगुजा अध्यक्ष फुलेश्वरी सिंह के नेतृत्व में शराब बंदी की मांग तथा कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति, रेडी टू ईट के निजीकरण करने का आरोप लगाकर विधायक लुण्डा डा प्रीतम राम के निवास का घेराव किया गया। महिला मोर्चा द्वारा बिलासपुर चौक से रैली निकालकर विधायक निवास जाकर धरना और घेराव किया गया। [15,16] भाजपा जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में भूपेश सरकार के लोक लुभावने वायदे के आधार पर जनता ने बहुमत दिया था लेकिन जनता के साथ सरकार ने छलने का काम किया है। स्वयं सहायता समूह की ऋण माफी की बात हो या रेडी टू ईट की बात हो प्रदेश की महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं। कई परिवार कर्ज के बोझ तले दब गए हैं उनकी आर्थिक स्थिति ब्याज से दयनीय हो गई है। भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष फुलेश्वरी सिंह ने कहा कि भूपेश सरकार ने पूर्ण शराबबंदी का वायदा किया था लेकिन प्रशासन खुद शराब बेच रही है। शराब के चलते छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ गढ़ बनते जा रहा है। [17,18] प्रदेश में महिला संबंधी बढ़े हैं। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और भूपेश सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भूपेश सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकारी बैंकों के निजीकरण के समर्थकों के तर्क कई कारणों से औचित्यपूर्ण नहीं ठहराए जा सकते। 1969 में जब पहली बार 14 निजी बैंकों का और 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय उसका मुख्य उद्देश्य सर्वसमावेशी विकास को बढ़ावा देना था। कृषि, लघु उद्योग, शिक्षा, निर्यात संवर्धन आदि को प्राथमिक महत्व का मानते हुए उनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से साख की उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी। [19,20] इसके अलावा अति सूक्ष्म ऋणों के लिए अत्यंत कम ब्याज दरों पर ऋण की उपलब्धता भी सार्वजनिक बैंकों से ही सुनिश्चित हुई थी। हालांकि तब से अभी तक परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निजी बैंकों को भी राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि तमाम नियमों, उपनियमों और निर्देशों के बावजूद सर्वसमावेशी विकास हेतु जितना काम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक करते हैं, निजी क्षेत्र के बैंक नहीं करते। नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद वित्तीय समावेश के उद्देश्य से जीरो बैलेंस वाले जनधन खाते खोले गए। अभी तक ऐसे 46 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं जिसके माध्यम से न केवल गरीब, आमजन की बैंकों तक पहुंच बन पाई है, बल्कि सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण इन्हीं जनधन खातों, जो आधार और मोबाईल फोन के साथ जुड़े हैं, संभव हुआ है। [21,22] किसान निधि का अंतरण हो अथवा 20 करोड़ महिलाओं को कोविड संबंधित नकद का अंतरण, यह सभी प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण ही हो पाया है। लेकिन आज जब निजी बैंकों का जमा और उधार में हिस्सा लगभग 37 प्रतिशत है, मात्र 10 प्रतिशत जनधन खाते ही निजी बैंकों द्वारा खोले गए। यही नहीं दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत 6 करोड़ महिलाओं को जीविका ऋण देने में भी सरकारी बैंकों और उन बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 90 प्रतिशत ऋण प्रदान किए गए। [23,24] इसी प्रकार अति लघु उद्यमों और व्यापारियों को ऋण देने का काम भी सरकारी बैंकों द्वारा ही किया जाता है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर निजी क्षेत्र के बैंकों के लाभ सरकारी बैंकों से ज्यादा होंगे ही, क्योंकि ये बैंक वित्तीय समावेशन के काम से कर्त्री काट लेते हैं। सरकारी बैंकों को सभी सरकारी योजनाओं को लागू करने की बाध्यता रहती ही है, ऐसे में निजी क्षेत्रों के बैंकों को इसलिए सक्षम मान लेना कि वे लाभ ज्यादा कमा रहे हैं, उचित नहीं होगा। यदि सरकारी बैंकों के कामकाज में से वित्तीय समावेशन और सोशल बैंकिंग हटा दी जाए तो उनके भी लाभ निजी बैंकों जैसे ही बढ़ सकते हैं। [25,26]

विचार-विमर्श

देशभर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्राइमरी और उच्च शिक्षा के संस्थानों को ऑनलाइन कक्षाएं लगाने का आदेश दिया था। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री आरपी निशंक ने यह भी कहा था कि 'जो छात्र ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और जिनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं लेना मुश्किल है उन्हें टीवी के ज़रिए 32 चैनलों के माध्यम से पाठ मुहैया कराए जाएंगे। [27,28] लेकिन सरकार की यह मुहिम फेल होते नजर आ रही है। इसी साल 22 जून को असम के चिरांग ज़िले के रहने वाले 16 साल के एक छात्र ने इसलिए खुदकुशी करली क्योंकि उसके पास ऑनलाइन क्लास और एग्जाम में हिस्सा लेने के लिए स्मार्ट फ़ोन नहीं था। इससे पहले 18 जून को केरल के मलप्पुरम जिले में 10वीं क्लास की छात्रा ने इसलिए आत्महत्या करली क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। उसे जो पढ़ाया जाता था वो उसे समझ नहीं आता था। लड़की के परिजनों का कहना है कि वो टीवी के माध्यम से ऑनलाइन क्लासिस किया करती थी और उस दौरान बिजली कट जाने से वो परेशान रहती थी। वो अपने

पिता से स्मार्टफोन दिलाने की मांग भी कर रही थी लेकिन लॉकडाउन में काम छिन जाने की वजह से उसके पिता उसे फोन नहीं दिला सके। [29,30] वहीं, 2 जून को भी केरल में ही ऑनलाइन क्लासिस में भाग ना ले पाने की वजह से एक और 10वीं कक्षा की छात्रा ने खुदकुशी करली थी। इन घटनाओं के बाद देश में ऑनलाइन एजुकेशन के स्वरूप और बुनियादी ढांचे को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल यह भी है कि क्या सरकार के लिए देश में ई शिक्षा को लागू करना आसान है? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2019 की एक रिपोर्ट बताती है कि 67 फ्रीसद पुरुष और महज 33 फ्रीसद महिलाएं ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। यह असमानता ग्रामीण इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है, जहां यह आंकड़ा पुरुषों में 72 फ्रीसद और महिलाओं में 28 फ्रीसद है। जेडर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत में लिंग समानता दुनिया में सबसे खराब है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तीकरण के उपायों के साथ भारत 153 देशों में से 112 वें स्थान पर है। उधर, लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों में इज़ाफ़ा देखने को मिला। राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में महिलाओं के खिलाफ हुए साइबर क्राइम की 54 शिकायतें मिली थी। वहीं, मार्च में यह आंकड़ा 37 और फरवरी में 21 का था। इस तरह की रिपोर्ट के बाद छात्राओं का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा आने के बाद साइबर अपराधों में बढ़ोतरी होगी। [27,26]

वहीं, दिव्या कहती हैं कि ऐसे समाज में जहां लड़कियों को फोन नहीं दिया जाता वहां ऑनलाइन शिक्षा लागू कर देना महिला विरोधी है। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देकर उसमें महिलाओं को शिक्षा से बाहर किया जा रहा है। वो बताती हैं कि अगर परिवार में लड़के या लड़की में से किसी एक को फोन या साधन देने की बात आएगी तो वो सबसे पहले लड़के को दिया जाएगा। मीणा कहते हैं कि हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली मौका देती है कि हम दूसरे तबकों से संबंध बना सकें और उनकी संस्कृति को जानने का मौका देती है। इसका काफी फायदा लड़कियों को मिल रहा था। वो मौजूदा शिक्षा प्रणाली के जरिए घरों से बाहर निकल रही थी और आसपास की चीजों के बारे में मालुमात हासिल कर रही थी लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद यह सब बदल जाएगा। इसके बाद लड़कियां फिर से अपने घरों में कैद हो जाएंगी और मिलने जुलने और जानने की जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। [23,24] इसके माध्यम से महिलाओं की आजादी पर भी हमला किया जा रहा है। साथ ही, पढ़ाई करने के लिए एक अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है। लेकिन सभी छात्रों के पास घर पर पढ़ने-लिखने के लिए एक शांत स्थान नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 37 फ्रीसद घरों में एक ही कमरा है। इससे साबित होता है कि यह कई लोगों के लिए इस अव्यवस्था में ऑनलाइन एजुकेशन लेना लकजरी होगा। इस वक्त जहां लाखों मजदूर अपनों बच्चों के साथ सड़कों पर निकल कर अपने घर पहुंचे हैं या पहुंचने वाले हैं उनके लिए कामकाज छिन जाने के बाद ऑनलाइन शिक्षा को अपनाना बहुत मुश्किल होगा। मीणा बताते हैं कि दिक्कत यह है कि सरकार परीक्षा के नाम पर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ला रही है। परीक्षा कराने के लिए हमारे पास विकल्प है। जैसे महाराष्ट्र और हैदराबाद की यूनिवर्सिटीज परीक्षा को लेकर जो कदम उठा रही है वो सरकार भी कर सकती है। इन यूनिवर्सिटीज ने छात्रों को उनके इंटरनल नम्बर के आधार पर प्रमोट करने की बात की है। दूसरा विकल्प है कि पिछले जो सेमेस्टर हुए हैं उनके मार्क्स के आधार पर एवरेज निकाला जाए और छात्रों को प्रमोट किया जाए। तीसरा विकल्प है कि इंटरनल और सेमेस्टर को मिलाकर छात्रों के एवरेज मार्क्स के आधार पर उन्हें अगली क्लास के लिए भेजा जाए। लेकिन यह एक समय-सीमा के तहत करना होगा, जो कि मुमकिन है। भारत में कहा जा रहा है कि यहां के एजुकेशन का मौजूदा ढांचा बदल कर उसकी जगह ऑनलाइन सिस्टम को लाया जा रहा है। इसके तहत यहां सिर्फ बच्चों को भर्ती करना ही टारगेट रह जाएगा। लेकिन उसका नतीजा क्या होगा सरकार को इस बारे में सुध ही नहीं है। [29,30]

परिणाम

जिला अस्पतालों को निजी क्षेत्र को सौंपने की नीति आयोग की योजना (NITI Aayog's plan to hand over district hospitals to the private sector) जन-स्वास्थ्य को मजबूत नहीं बल्कि और अधिक कमजोर बनाएगी। नीति आयोग के अनुसार, उसका यह सार्वजनिक – निजी – साझेदारी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) प्रस्ताव वैश्विक अनुभव पर आधारित है। पर हमारा मानना है कि सार्वजनिक – निजी – साझेदारी कुल मिला कर निजीकरण ही है और समाज के हाशिये पर रह रहे महिलाओं इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, और सरकारी सेवाओं के निजीकरण को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए सोशललिस्ट पार्टी (इंडिया), जन-स्वास्थ्य प्रणाली के निजीकरण के हर प्रयास का विरोध करती है।

"सरकारी बैंकों का डिस्इन्वेस्टमेंट यानि निजीकरण बैंक कर्मियों के साथ गरीब महिलाओं जनता के लिए बहुत घातक कदम होगा। आपको को क्या लगता है जो गरीब जनता आईसीआईसीआईसी और एचडीएफसी बैंकों में जाएगी जहां खाता ही 5000 या 10000 रुपए से खुलता है। आज की तारीख में सारी योजनाएं सरकारी बैंकों से होकर जाती हैं। 97 फ्रीसदी जनधन खाते सरकारी बैंकों में हैं तो 99 फ्रीसदी मुद्रा लोन सरकारी बैंकों ने दिया है। जब निजीकरण होगा तो इनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी।" संदीप सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस (INBOC) और ऑल इंडिया बैंक और बड़ौदा ऑफिसर्स एसोसिएशन के जोनल सेक्रेटरी (लखनऊ जोन) ने गांव कनेक्शन को निजीकरण के नुकसान गिनाए। [31]

निजीकरण लिंग-तटस्थ नहीं है। यह श्रम बाजार और घर में महिलाओं की समानता की ओर बढ़ने की धमकी देता है। श्रम बाजार में, निजीकरण का अर्थ आमतौर पर महिला श्रमिकों के लिए कम मजदूरी, कम कार्यस्थल अधिकार, कम स्वास्थ्य और कल्याण लाभ, कोई पेंशन कवरेज नहीं, कम अनुमानित काम के घंटे, अधिक अनिश्चित रोजगार, अधिक काम का बोझ और आम तौर पर अधिक शोषक काम करने की स्थिति है। निजीकरण एक ऐसा शब्द है जिसमें कई विशिष्ट प्रथाएं शामिल हैं। आम तौर पर इसका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में काम के हस्तांतरण को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसमें इससे कहीं अधिक शामिल है, जिसमें एक सार्वजनिक, भुगतान किए गए क्षेत्र से घर के निजी, अवैतनिक क्षेत्र में काम का हस्तांतरण शामिल है। यह सार्वजनिक सेवाओं में कटौती का परिणाम हो सकता है या बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए उन सेवाओं के बढ़ने और विस्तार करने में विफलता का परिणाम हो सकता है। श्रम बाजार में, उप-अनुबंध निजीकरण के सबसे सामान्य रूपों में से एक है, जिसके तहत एक निजी कंपनी को काम करने के लिए एक अनुबंध दिया जाता है। कनाडा में सरकार के सभी स्तरों पर उप-अनुबंध आम है - संघीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों द्वारा - जहां काम या सेवाओं की जिम्मेदारी सरकार से एक निजी कंपनी को हस्तांतरित की जाती है।

निजीकरण (और आउटसोर्सिंग) कम लागत, विशेष रूप से श्रम लागत के लिए किया जाता है। निर्णय को अक्सर यह दावा करके उचित ठहराया जाता है कि कुछ सेवाएं और उन्हें करने वाले कर्मचारी सहायक हैं या मुख्य सेवा या कार्य के अभिन्न अंग नहीं हैं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य देखभाल पर रोमानो आयोग, जो निजी स्वास्थ्य देखभाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, ने स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं (सफाई, भोजन, कपड़े धोने) के निजीकरण को इस आधार पर स्वीकार्य माना कि वे सहायक थे और स्वास्थ्य का अभिन्न अंग नहीं थे- देखभाल वितरण प्रणाली। और जनरल मोटर्स द्वारा अपने ओशावा संयंत्र में उप-अनुबंध कस्टोडियल कार्य द्वारा श्रम लागत कम करने का हालिया निर्णय इसी तर्क पर आधारित है। इन निर्णयों के पीछे यह तर्क और धारणाएँ दोषपूर्ण हैं और श्रमिकों, विशेष रूप से महिला श्रमिकों और रंग की महिला श्रमिकों के लिए गंभीर परिणाम हैं, जो अक्सर निम्न-स्तरीय नौकरियों में नियोजित होते हैं। कनाडा के इतिहास में निजीकरण के सबसे बड़े मामले की जांच करने वाले शोध से पता चला कि यह नीति इन महिलाओं के लिए कितनी विनाशकारी है। [32]

2003 और 2004 में ब्रिटिश कोलंबिया में अस्पतालों और दीर्घकालिक देखभाल केंद्रों में समर्थन सेवाओं के उप-अनुबंध ने कनाडा के इतिहास में निजीकरण की सबसे बड़ी लहर का प्रतिनिधित्व किया। निचली मुख्य भूमि और दक्षिणी वैक्यूवर् द्वीप में अस्पतालों और दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं द्वारा नियोजित लगभग 8,500 सफाई कर्मचारियों, खाद्य सेवा, कपड़े धोने और सुरक्षा कर्मचारियों ने अक्टूबर, 2003 और जुलाई, 2004 के बीच अनुबंध करने के लिए अपनी नौकरी खो दी।

इन कामगारों का प्रतिनिधित्व कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉइज के बीसी स्वास्थ्य विभाग अस्पताल कर्मचारी संघ द्वारा किया गया था। आवश्यकता पड़ने पर हड़ताल की कार्यवाही करने के लिए तैयार एक मजबूत संघ के निर्माण और महिला श्रमिकों के लिए कम वेतन को संबोधित करने के इतिहास के परिणामस्वरूप, एचईयू ने अपने सामूहिक समझौते में अच्छा वेतन और लाभ हासिल किया था। इंटरनेशनल वुडवर्कर्स ऑफ अमेरिका (IWA) ने अनुबंधित-आउट श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निजी ठेकेदारों के साथ एक प्रिय सौदे पर बातचीत की।

जब नौकरियों का अनुबंध किया गया तो वे कनाडा में सबसे अधिक वेतन पाने वाले अस्पताल के हाउसकीपर से सबसे कम वेतन पाने वाले हो गए। उनका वेतन लगभग 20 डॉलर प्रति घंटे से घटाकर 10.50 डॉलर प्रति घंटा कर दिया गया। प्रोफेसर मार्जोरी कोहेन की गणना के अनुसार, यह उनके वेतन में लगभग 30 साल के रोलबैक का प्रतिनिधित्व करता है। और हजारों व्यक्तियों, मुख्य रूप से महिलाओं ने अपनी नौकरी खो दी। [30]

अन्य महत्वपूर्ण कार्यस्थल अधिकारों और लाभों को भी अनुबंधित करके काट दिया गया था। पेंशन योजना समाप्त कर दी गई थी। सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक अतिरिक्त दिन के साथ पांच साल के बाद 20 दिनों के स्तर से छुट्टियों को कम से कम कानूनी रूप से स्वीकार्य, रोजगार मानक अधिनियम की आवश्यकताओं में काट दिया गया था। सत्रह सप्ताह का भुगतान किया गया पैतृक अवकाश समाप्त कर दिया गया था। प्रति सप्ताह 20 घंटे से कम काम करने वालों के लिए लाभ में कटौती की गई। जिन लोगों ने लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त काम किया, उन्हें अब प्रीमियम के सह-भुगतान का सामना करना पड़ा। लंबी अवधि की विकलांगता योजना और चोट-पर-कर्तव्य अवकाश को समाप्त कर दिया गया। प्रति माह 1.5 दिनों के आधार पर संचित बीमार-अवकाश योजना को हर छह महीने में दो दिन की बीमारी की छुट्टी में वापस कर दिया गया था, जिसमें छुट्टी जमा करने की कोई क्षमता नहीं थी।

साथ ही, काम के घंटों का निर्धारण बहुत कम अनुमानित हो गया। एचईयू अनुबंध ने काम के घंटों में बदलाव के लिए ओवरटाइम भुगतान के साथ, वरिष्ठता और स्थिति के आधार पर बदलाव का 14 दिनों का नोटिस प्रदान किया था। उप-अनुबंधित श्रमिकों के लिए IWA द्वारा बातचीत किए गए सामूहिक समझौते ने काम के घंटों में बदलाव के लिए काम के घंटे, कोई शेड्यूल और कोई ओवरटाइम की कोई गारंटी नहीं दी। अप्रत्याशित काम के घंटे चाइल्डकैअर या परिवार और दोस्तों के साथ समय की योजना बनाने में कहर बरपाते हैं।[31]

निष्कर्ष

नए उप-अनुबंधित शासन के तहत साक्षात्कार किए गए श्रमिकों ने गहन, थकाऊ और खतरनाक कार्यभार का खुलासा किया। एक महिला कार्यकर्ता ने बताया: "पिछले कुछ महीनों से मैंने पिछले 15 मिनट का ब्रेक नहीं लिया है।" एक अन्य ने कहा: "अगर मैं अपना 30 मिनट का लंच ब्रेक लेता हूँ तो मैं कभी भी काम खत्म नहीं करूँगा। मैं या तो अधिक समय तक रुकता हूँ या इसे पूरा करने के लिए जल्दी करता हूँ।" एक तीसरी महिला ने समझाया: "अगर काम नहीं किया गया, तो आपको शिकायतों के कारण निकाल दिया जाएगा। ठेकेदार हमें बहुत अधिक करने के लिए प्रेरित करता है। यह अपमानजनक है।" परिस्थितियों के बावजूद, कई कर्मचारी अधिक घंटे काम चाहते थे, क्योंकि साक्षात्कार में शामिल आधे लोगों ने प्रति सप्ताह 20 से 37.5 घंटे के बीच काम किया - पूर्ण और अंशकालिक के बीच एक गोथूलि क्षेत्र। कम वेतन के साथ संयुक्त कुछ घंटों का मतलब वेतन अपर्याप्त था। अधिकांश लोग गरीबी रेखा से बहुत नीचे रहते थे, और साक्षात्कार में लिए गए लगभग आधे श्रमिकों के पास कम से कम एक अन्य नौकरी थी। उप-ठेकेदार श्रमिकों ने थकावट और दर्द की शिकायत की। साक्षात्कार में शामिल 24 श्रमिकों में से एक को छोड़कर सभी ने प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों की सूचना दी, जैसे कि व्यथा, जकड़न, सुन्नता, माइग्रेन, मांसपेशियों में खिंचाव, कटना और जलन - और यह निजी ठेकेदारों के लिए काम करने के एक वर्ष से भी कम समय में था। इन गंभीर स्वास्थ्य शिकायतों के बावजूद, लगभग आधे लोगों ने बीमार होने का समय नहीं लिया, या तो उन्हें डर था कि वे अपनी नौकरी खो देंगे या क्योंकि वे कुछ बीमार दिनों का भुगतान नहीं कर सकते थे।[32]

अपने चालीसवें वर्ष में एक महिला ने कहा कि वह खुद को 50 साल की उम्र में काम करते हुए नहीं देख सकती क्योंकि काम बहुत भारी था। "हर दिन, काम के बोझ के कारण, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। मैं अभी बहुत थक गया हूँ।" दो नौकरियों वाली 40 वर्षीय एकल माँ ने कहा, "जब मैं बिस्तर पर घर जाती हूँ तो मैं सपाट हो जाती हूँ।" उदास, क्रोधित, परेशान और निराश ये महिलाएं इन परिस्थितियों में काम करना कैसा महसूस करती थीं। ये भावनाएं उन लोगों के लिए सबसे गंभीर थीं जो पूर्व एचईयू सदस्य थे और वेतन में बड़ी गिरावट, कार्यभार में वृद्धि, कई कार्यस्थल अधिकारों के नुकसान का अनुभव किया था, और जो सहकर्मियों और अपने पूर्व पर्यवेक्षकों के साथ बेहतर संबंधों से चूक गए थे। इन भावनाओं के बावजूद उनका गुस्सा और तनाव अंदर ही अंदर बंद था। जैसा कि एक महिला ने कहा: "मैं शांत हो जाती हूँ। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। कभी-कभी मैं रोता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर ही अंदर विस्फोट करने जा रहा हूँ। मैं असहमत हूँ, लेकिन सुनो और कुछ मत कहो।" एक अन्य महिला ने खुलासा किया, "मुझे गुस्सा आता है, लेकिन इसे न दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि मैं अपने पर्यवेक्षक को यह जानने से डरती हूँ। मैं यह नौकरी नहीं खो सकता।"

आश्चर्य नहीं कि काम के बारे में उनकी भावनाएँ उनके घरेलू जीवन में फैल गईं। एक महिला ने अफसोस जताया कि "बच्चों के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। मेरे पास कोई ऊर्जा नहीं है। मैं अभी घर जाकर सोता हूँ। मैं थक गया हूँ और मेरे पास दोस्त नहीं हैं। मैं अपनी बेटी को कुछ करने के लिए कहता हूँ, लेकिन मैं उसे जन्मदिन नहीं दे सकता या उसके लिए उपहार भी नहीं खरीद सकता। इन महिलाओं को अपने परिवार के साथ समय और ऊर्जा खर्च करने में सक्षम नहीं होने या अपने बच्चों को जो चीजें चाहिए वह प्रदान करने में सक्षम नहीं होने के लिए जबरदस्त अपराधबोध का अनुभव हुआ। उनके बच्चों को बिना कुछ करना पड़ा, कई ने परिवार की मदद करने की कोशिश करने के लिए किशोरों के रूप में काम करना शुरू कर दिया, और बड़े लोगों को काम खोजने के लिए स्कूल जाने की योजना छोड़नी पड़ी। मनोरंजन और छुट्टियाँ कम कर दी गईं और कुछ को सस्ता आवास खोजने के लिए स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।[32]

इन उप-अनुबंधित नौकरियों में काम करने वाली महिलाएं मुख्य रूप से अप्रवासी थीं, और उनके काम के प्रभाव ने विदेशों में उनके विस्तारित परिवारों को प्रभावित किया। कनाडा में उनकी कठिन परिस्थितियों के बावजूद, कई ने अपने विस्तारित परिवारों का समर्थन करने के लिए धन भेजना जारी रखा, जिनके सदस्यों को स्नातक होने के बाद आप्रवासन की आशा के साथ स्कूल में जीवित रहने या जारी रखने के लिए धन की आवश्यकता थी। जैसा कि एक महिला, जो अब अपने पूर्व एचईयू वेतन के लिए तीन नौकरियों में काम कर रही थी, ने समझाया, "हम कम आय के साथ भी अब उतनी ही राशि भेजते हैं। हमें फर्क करने के लिए और नौकरियों की जरूरत है। फिर भी, यह अभी भी उनके लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। वे यहां की स्थिति को नहीं समझते हैं।"

निजीकरण के इस मामले के अध्ययन से महिलाओं के लिए कई प्रतिकूल प्रभावों का पता चलता है। निजीकरण ने महिलाओं के लिए हजारों अच्छी नौकरियों को समाप्त कर दिया, उन्हें 30 वर्षों में प्राप्त मजदूरी और अन्य महत्वपूर्ण कार्यस्थल अधिकारों को कम करके थकाऊ और खतरनाक काम के साथ बदल दिया। इसने रंग की अप्रवासी महिलाओं को इन शोषणकारी स्थितियों के लिए भेजा, उन्हें नस्ल और जातीयता के आधार पर विभाजन द्वारा चिह्नित काम पर द्वितीय श्रेणी के नागरिकों की भूमिका में मजबूत किया। इसने उनके बच्चों के लिए अधिक घरेलू संघर्ष और बलिदान उत्पन्न किए, और सामुदायिक और नागरिक गतिविधियों में भाग लेने की उनकी अपनी क्षमता को कम कर दिया। संक्षेप में, इसने इन महिलाओं के लिए कार्यस्थल या घर पर आगे बढ़ना कठिन बना दिया।

इस केस स्टडी से पता चलता है कि निजीकरण और अनुबंध करने से असमानता अधिक होती है। यह श्रमिकों के एक समूह (तथाकथित सहायक कर्मचारी जिनकी नौकरियां उप-अनुबंधित हैं) और शेष कर्मचारियों के बीच मजदूरी, कार्यस्थल के अधिकारों और काम करने की स्थिति में अंतर को चौड़ा करता है। यह दृश्यमान अल्पसंख्यक, अप्रवासी श्रमिकों के लिए गरीबी को मजबूत करता है, जो ऐसी नौकरियों में नियोजित होते हैं जिनकी बेरोजगारी की उच्च दर और काम के लिए कम विकल्प होते हैं। कम कार्यस्थल अधिकार, शोषणकारी, थकाऊ काम और कम वेतन इन श्रमिकों के सामाजिक बहिष्कार के लिए स्थितियां पैदा करते हैं, समाज में यौन और नस्लीय विभाजन को मजबूत करते हैं।

इस मामले में अच्छी खबर यह है कि बीसी श्रम संबंध बोर्ड ने कमजोर सामूहिक समझौतों को रद्द कर दिया, जो कि आईडब्ल्यूए ने निजी ठेकेदारों के साथ इस आधार पर हस्ताक्षर किए थे कि कोई कर्मचारी इनपुट या अनुसमर्थन नहीं था। और HEU इन श्रमिकों को संगठित करने और एक नए सामूहिक समझौते पर हस्ताक्षर करने में सफल रहा जिससे उनके वेतन और कार्यस्थल के अधिकारों में सुधार हुआ। लेकिन नए सामूहिक समझौतों ने सभी खोई हुई जमीन को वापस नहीं पाया, और यह अभी भी उन मानकों के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है जो इन श्रमिकों ने पहले प्राप्त किए थे।[32]

संदर्भ

1. चौधरी, एफ. एल. "भ्रष्ट नौकरशाही और कर प्रवर्तन का निजीकरण", 2006: पाठक सामबेश, ढाका
2. ↑ "Musselburgh Co-op in crisis as privatization bid fails". Co-operative News. 2005-11-01. मूल से 10 मार्च 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2008-05-21.
3. ↑ Edwards, Ruth Dudley (1995). The Pursuit of Reason: The Economist 1843-1993. Harvard Business School Press. पृ 946. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0-87584-608-4.
4. ↑ तुलना Bel, Germà (2006). "Retrospectives: The Coining of 'Privatisation' and Germany's National Socialist Party". Journal of Economic Perspectives. 20 (3): 187–194. डीओआइ:10.1257/jep.20.3.187.
5. ↑ डेविड पार्कर द्वारा निजीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तिका, डेविड एस. साल
6. ↑ सेंट्रल यूरोप के बड़े पैमाने पर उत्पादन निजीकरण Archived 2009-10-18 at the Wayback Machine, हेरिटेज लेक्चर #352
7. ↑ डैंगेवियरेन (2006) "गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में निजीकरण पर पुनर्चर्चा". अंतर्राष्ट्रीय विकास का जर्नल खंड 18, 469-488
8. ↑ "Privatisation in Competitive Sectors: The Record to Date, World Bank Policy Research Working Paper No. 2860". John Nellis and Sunita Kikeri. World Bank. June 2002. मूल से 11 मार्च 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 नवंबर 2010.
9. ↑ "From State To Market: A Survey Of Empirical Studies On Privatisation" (PDF). William L. Megginson and Jeffrey M. Netter. Journal of Economic Literature. June 2001. मूल (PDF) से 2 अक्टूबर 2005 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 नवंबर 2010.
10. "Winners and Losers: Assessing the Distributional Impact of Privatisation, CGD Working Paper No 6" (PDF). Nancy Birdsall & John Nellis. Center for Global Development. March 9, 2006.
11. ताकाहारा, "सभी आंखें जापान पोस्ट पर "Faiola, Anthony (2005-10-15). "Japan Approves Postal Privatization". Washington Post. The Washington Post Company. पृ A10. मूल से 4 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2007-02-09.
12. ↑ विलियम एल. मेगिन्सन द्वारा निजीकरण के वित्तीय अर्थशास्त्र, पृष्ठ 205-206

13. अलेक्जेंडर, जेसन. **2009**. शास्त्रीय व्यावहारिकता के लेंस के माध्यम से अनुबंध: स्थानीय सरकारी अनुबंध का अन्वेषण. अनुप्रयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं. टेक्सास राज्य विश्वविद्यालय. <https://web.archive.org/web/20100621122134/http://ecommons.txstate.edu/arp/288/>.
14. डोवाल्लिना, जेसिका. **2006**. आउट प्रोसेस करार में मिले नैतिक मुद्दों का आकलन. अनुप्रयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं. टेक्सास राज्य विश्वविद्यालय. <https://web.archive.org/web/20100625140633/http://ecommons.txstate.edu/arp/108/>.
15. सेजेर्फेल्ड, फ्रेडरिक. **2006**. जल बिक्री के लिए: दुनिया के जल संकट को व्यापार और बाजार कैसे हल कर सकते हैं। स्टॉकहोम नेटवर्क. <https://web.archive.org/web/20120301074135/http://www.stockholm-network.org/downloads/events/d41d8cd9-Amigo%20Segerfeldt.pdf>
16. बर्नार्ड ब्लैक एट अल., 'रूसी निजीकरण और निगमित प्रशासन: क्या गलत हो गया? (2000) 52 स्टैनफोर्ड लॉ 1731 की समीक्षा
17. जुल्लो, रोलाण्ड. **(2009)**. क्या वित्तीय तनाव निजीकरण पैदा करता है? निजी और इंटरमुनीसिपल कॉन्ट्रैक्ट के सहसंबद्ध, 1992-2002.
18. कोसर, केविन आर. **(2006)**, "निजीकरण और संघीय सरकार: एक परिचय", कांग्रेस संबंधी अनुसंधान सेवा से रिपोर्ट
19. बेल, जर्मा **(2006)**, "द कौयेनिंग ऑफ़ 'प्राइवाइज़ेशन' एंड जर्मनिज़ नैशनल सोशलिस्ट पार्टी", जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव 20(3), 187-194
20. क्लार्क, थॉमस (एड.) **(1994)** "अंतर्राष्ट्रीय निजीकरण: रणनीतियां और आचरण" बर्लिन और न्यूयॉर्क: वॉल्टर डे ग्रुटर, ISBN 3-11-013569-8
21. क्लार्क, थॉमस और पितेलिस, क्रिस्टोस (एड्स.) **(1995)** "निजीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था" लंदन और न्यूयॉर्क: रूटलेज, ISBN 0-415-12705-X
22. निको पेरोन **(2002)** इकोनॉमिया पब्लिका रिमोसा, मिलान, गिउफ्रे ISBN 88-14-10088-8
23. मेयर, फ्लोरियन **(2006)** Vom Niedergang des unternehmerisch tätigen Staates: Privatisierungspolitik in Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland, वीएस वर्लग, विस्बडेन, ISBN 3-531-14918-0
24. मेगिन्सन और नेटर, राज्य से लेकर बाजार तक: निजीकरण पर प्रायोगिक अध्ययन के एक सर्वेक्षण, आर्थिक साहित्य 39(2) का पत्रिका, जून **2001**, 321-89.
25. जूलियट डि'सूजा, विलियम एल. मेगिन्सन (1999), "1990 दशक के दौरान निजीकरण फर्मों के वित्तीय और ऑपरेटिंग प्रदर्शन", जर्नल ऑफ़ फाइनेंस अगस्त **1999**
26. वॉन हायेक, फ्रेडरिक, **(1960)** द कंस्टिट्यूशन ऑफ़ लिबर्टी
27. स्मिथ, एडम **(1994)** द वेल्थ ऑफ़ नेशंस
28. स्टिग्लिटज़, जोसेफ ग्लोबलाइज़ेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स
29. David T. Beito, Peter Gordon, and Alexander Tabarrok (editors); foreword by Paul Johnson **(2002)**. The voluntary city: choice, community, and civil society. Ann Arbor: University of Michigan Press/The Independent Institute. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0-472-08837-8.
30. वॉन वीज़सैकर, अर्नस्ट, ओरान यंग और मैथियस फिगर (संपादक): निजीकरण करने के लिए सीमा. अर्थस्कैन, लंदन **2005** ISBN 1-84407-177-4
31. जेब स्प्रैग, **2007**. हैटी: वर्कर्स प्रोटेस्ट प्राइवाइज़ेशन लेऑफ़्स. इंटर प्रेस सेवा.
32. रोजर एल. केम्प, पीएचडी (PhD), "निजीकरण: निजी क्षेत्र द्वारा लोक सेवाओं के प्रावधान" मैकफ़ारलैंड एंड कं., जेफरसन, एनसी, अमरीका और लंदन, ब्रिटेन, **2007**.